© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एवं सिंगापुर

दिलीप कुमार वर्मा
शोध छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ

दक्षिण–पूर्व एशिया, चीन के दक्षिण में वियतनाम से इण्डोनेशिया तक एवं भारत के पूर्व में बर्मा से फिलीपीन्स तक के क्षेत्र का सामूहिक नाम है। इस क्षेत्र में अनेक द्वीप और एशिया महाद्वीप का दक्षिणी भूखण्ड भी सम्मिलित है जिनमें बर्मा, थाईलैण्ड, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया तथा अनेक द्वीप श्रृंखलाएँ हैं जिनका विस्तार फिलीपीन्स तक है। इस क्षेत्र की एकरुपता द्वितीय विश्व युद्ध के समय .ष्टिगोचर हुई, जब जापान की विजयवाहिनी सेना ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया एवं मित्र राष्ट्रों ने प्रत्युत्तर में अगस्त 1943 ई0 में क्यूबेक सम्मेलन के द्वारा एडमिरल माउण्टबेटन की अधीनता में 'दक्षिण–पूर्व एशिया कमान' की स्थापना की। दक्षिण–पूर्व एशिया सामरिक एवं भौगोलिक रुप से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। यह हिन्द महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाने वाले समुद्री मार्ग पर स्थित है और एशिया व आस्ट्रेलिया के मध्य एक प्राकृतिक पुल का कार्य करता है। आर्थिक दृष्टि से भी दक्षिण–पूर्व एशिया बहुत समृद्ध है। चावल, टिन, रबड़, नारियल एवं पेट्रोलियम आदि प्रचुर मात्रा में यहाँ पाया जाता है।

सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप है जो मलय प्रायद्वीप के दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र से थोड़ा पृथक एवं मलक्का जलसंधि के पूर्वी तट पर अवस्थित है। दक्षिण–पूर्व एशिया के प्रायद्वीपीय क्षेत्र एवं द्वीप समूहों के क्षेत्रों के लगभग मध्य में इसकी अवस्थिति ने इसे नौसैनिक आधार एवं प्रमुख आन्त्रप ;म्दजतमचवजद्ध केन्द्र के रुप में विकसित किया है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पाँच प्रमुख क्षेत्रों (क्षेत्रीय आन्त्रप व्यापार, निर्यात उन्मुख विनिर्माण, पेट्रोलियम शोधन एवं शिपिंग, घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए सामानों एवं सेवा का उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए विशेष सेवाओं का प्रावधान जैसे बैंकिंग, वित्त एवं दूरसंचार के क्षेत्र में) पर अधारित है। विश्व बैंक द्वारा जारी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018' वार्षिक रिपोर्ट में सिंगापुर दूसरे जबकि भारत 100वें स्थान पर है वहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था सूचकांक 2016–17 में सिंगापुर दूसरे तथा भारत 39वें स्थान पर है।

भारत–सिंगापुर के बीच व्यापार प्रमुख रुप से वस्त्र और यार्न, कीमती पत्थर एवं मोती, कार्यालय एवं डेटा मशीन के भाग, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मछली एवं मछली उत्पादों, फल एवं सब्जियाँ (जिन्हें भारत निर्यात करता है) तथा पेट्रोलियम उत्पादों, मशीनरी, कार्यालय एवं डेटा प्रॉसेसिंग मशीन, धातु अयस्क एवं स्क्रैप, कार्बानिक रासायन, प्राथमिक प्लास्टिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों (जिन्हें भारत आयात करता है) आदि का होता है।

इस प्रकार सिंगापुर की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति, भारत के हित के लिए आर्थिक एवं सामरिक दोनों रुपों से महत्वपूर्ण है।

भारत–सिंगापुर संबंध

भारत और सिंगापुर ''वृहत भारत'' के सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र का हिस्सा होने के साथ–साथ सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंधों को प्राचीन काल से ही साझा करते रहे हैं, जो भारत एवं सिंगापुर के बीच संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करता है। वर्तमान भारत–सिंगापुर संबंध, ब्रिटेन द्वारा सिंगापुर की स्थापना के साथ प्रारम्भ हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 1819 ई0 में सर थामस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने एक ब्रिटिश व्यापार पोस्ट के रुप में सिंगापुर के दक्षिणी हिस्से को विकसित करने के लिए जोहोर के सुल्तान हुसैन शाह के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1826 ई0 में सिंगापुर के क्षेत्रीय राजधानी बनने पर, ब्रिटिश भारत के अधिकार क्षेत्र में जलडमरु बस्तियों का हिस्सा बन गया। भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आजाद हिन्द फौज के गठन का दूसरा चरण यहिं से ही प्रारम्भ हुआ जब 24 अक्टूबर 1943 ई0 को सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार ''आजाद हिंद सरकार'' की स्थापना हुई तथा सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। सिंगापुर से ही सुभाषचंद्र बोस ने ''दिल्ली चलो'' का प्रसिद्ध नारा दिया था। औपनिवेशिक शासन संबंध तथा भारतीय लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति (कुल जनसंख्या का 9.2:) भारत और सिंगापुर के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जहाँ भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित थी वहीं सिंगापुर का जुड़ाव पश्चिमी देशों के साथ था जिसके कारण भारत–सिंगापुर संबंध तब तक अच्छे नहीं रहे जब तक कि सिंगापुर एक स्वतंत्र देश के रुप में अस्तित्व में आ नहीं गया। 24 अगस्त 1965 ई0 को सिंगापुर को आजादी मिलने के बाद भारत आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के आधार पर राजनयिक संबंधों की स्थापना करने वाले देशों में से एक था। 1965 से 1970 ई0 के बीच भारत–सिंगापुर संबंधों में नया मोड़ तब आया जब ब्रिटिश फौज द्वारा क्रमिक रुप से दक्षिण–पूर्व एशिया को छोड़ने से वहाँ उत्पन्न शक्ति शून्यता की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने कहा था कि ''ब्रिटिश फौज की क्रमिक वापसी इस क्षेत्र में शक्ति शून्यता स्थापित करेगी–शून्यता मतलब अस्थिरता।'' ऐसी स्थिति में मलेशिया और इण्डोनेशिया में जहाँ चीन द्वारा कम्यूनिस्ट विद्रोहियों को सहायता दी जा रही थी ऐसे देशों से घिरे होने के कारण सिंगापुर जैसे गैर साम्यवादी नव स्वतंत्र देश को सबसे ज्यादा खतरा था। प्रधानमंत्री ली ने 1966 ई0 में नयी दिल्ली की यात्रा के दौरान इन्दिरा गाँधी से दृढ़ता पूर्वक आग्रह किया कि वे दक्षिण–पूर्व एशिया में भारत द्वारा बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने पर विचार करें। परन्तु भारत–चीन सीमा विवाद के कारण इन्दिरा गाँधी ने दक्षिण–पूर्व एशिया में सीधे हस्तक्षेप करने में संकोच किया। 1968 ई0 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की सिंगापुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने दोनों देशों की महत्वपूर्ण समानताओं को स्वीकार किया तथा दक्षिण–पूर्व एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका का समर्थन किया। सिंगापुर ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की दावेदारी तथा 1965 ई0 के भारत–पाकिस्तान युद्ध में भारत का समर्थन किया।

1970 से 1990 ई0 तक भारत–सिंगाापुर संबंध पूरी तरह शीतयुद्ध से प्रभावित रहा जिसके कारण जहाँ एक ओर भारत का झुकाव सोवियत संघ के प्रति रहा वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी बना रहा। इस प्रकार आधिकारिक स्तर पर दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बने रहे लेकिन वैचारिक स्तर पर विभिन्नता के कारण संबंधों में विशेष प्रगति नही हो पायी।

भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी एवं सिंगापुर

1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति एवं भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण भारत ने अपनी आन्तरिक एवं वाह्य नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इसी समय भारत ने अपनी विदेश नीति का रुख पश्चिमी देशों से हटाकर दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों की ओर मोड़ा जो भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। इस गतिशील पृष्ठभूमि पर भारत ने स्वयं के भावी विशाल रूप की खोज में 'पूर्व की ओर देखो नीति' का प्रतिपादन किया था।

भारत की 'पूर्व की ओर देखो नीति' का संबंध 1990 ई0 के प्रारम्भिक वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय तंत्र के बदले हुए भू–राजनीतिक एवं आर्थिक सन्दर्भ से था। यह नीति सर्वप्रथम 1991 ई0 नरसिम्हा राव सरकार द्वारा प्रतिपादित की गई थी। 'पूर्व की ओर देखो नीति' एक बहुआयामी तथा बहुपक्षीय दृष्टिकोण पर अधारित नीति थी जिसका संबंध इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यक्तिगत सामरिक संबंध के साथ–साथ आसियान देशों के साथ राजनीतिक संबंध बनाने तथा आर्थिक रुप से इस क्षेत्र से जुड़ने से था। इसकी उत्पत्ति सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक मदद के क्रमिक रूप से कम होने, प्रथम खाड़ी युद्ध के कारण तेल कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से तथा निर्यात में कमी के कारण भुगतान संतुलन की समस्या से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत को आंतरिक स्तर पर मुक्त बाजार कार्यक्रम को समर्थन देने और बाहर दूसरे देशों में नए बाजार व आर्थिक सहयोगी खोजने पर बाध्य कर दिया। भारत की विदेश नीति के दायरे में इस नीति के आने से भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच लम्बा खिंचा अलगाव सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। तीव्र गति से विकसित होते आसियान के देशों जिन्हें 'एशियन टाइगर' कहा जाने लगा था, से भारत का जुड़ना आवश्यक हो गया जिसका प्रभाव भारत एवं सिंगापुर संबंधों पर व्यापक रुप से पड़ा।

आंतरिक स्तर पर, 1990 के प्रारम्भिक वर्षों में भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने भारत की अर्थव्यवस्था में सिंगापुर की महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए संभावनाओं के अवसर को खोलने का कार्य किया जिसने सिंगापुर के निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया। उदाहरण के लिए, इण्टरकॉन्टीनेन्टल फॉरेस्ट प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड जैसी सिंगापुर की व्यवसायिक कम्पनी ने निवेश के अवसर के लिए भारतीय बाजार का सर्वेक्षण किया। सिंगापुर व्यापार विकास बोर्ड के अनुसार वर्ष 1994 के पहले 11 महीनों में भारत–सिंगापुर द्विपक्षीय व्यापार 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच चुका था।

फरवरी, 1993 ई0 में सिंगापुर के दूरसंचार तथा कला एवं वैदेशिक मामलों के दूसरे मंत्री जार्ज येवो ने एक व्यवसायिक प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली एवं भारत के अन्य शहरों की 12 दिवसीय यात्रा का प्रतिनिधित्व किया जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग एवं पर्यटन में संयुक्त उद्यम, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, रियल स्टेट बिजनेस, वित्तीय सेवाएँ, शिपिंग, वेयर हाउसिंग आदि क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाना था। बंगलौर के निकट सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करना, दोनों देशों के बीच वार्ताओं के प्रमुख परिणामों में से एक था। इस परियोजना को कर्नाटक सरकार, भारत के टाटा समूह तथा सिंगापुर के निवेशको के एक संघटन के भागीदारी के रुप में की गयी। यह पार्क भारत में सिंगापुर की प्रमुख परियोजना के रुप में प्रचारित था। सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोह चोक तोंग ने भारत के आर्थिक सुधार की नीति में रुचि दिखायी तथा 1994 ई0 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में भारत आये।

1998 ई0 के एशियायी वित्तीय संकट से दक्षिण–पूर्व एशिया के उबरने के बाद भारत–सिंगापुर के आर्थिक संबंध प्रगाढ़ होने आरम्भ हो गये। इस वित्तीय संकट से सिंगापुर अन्य दक्षिण–पूर्व एशियायी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत सुरक्षित बचा रहा। जिसके कारण भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्तावित किया कि सिंगापुर एवं भारत मिलकर 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते ;ब्म्ब्।द्ध को एक साथ स्थापित करने की क्षमता का आकलन करके अपनी आर्थिक भागीरदारी को बढ़ाएँ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री गोह के अनुसार व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के द्वारा सिंगापुर, भारत के लिए दक्षिण–पूर्व एशिया के लिए प्रवेश द्वार तथा भारत वं चीन के बीच व्यापार एवं वित्तीय मध्यस्थ के रुप में कार्य करेगा।

प्रधानमंत्री गोह चोक तोंग ने 8 अप्रैल 2003 ई0 को नयी दिल्ली में दिये गये अपने भाषण में कहा कि ''भारत इस शताब्दी में दक्षिण–पूर्व एशिया की स्थिरता एवं प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा''। प्रधानमंत्री गोह ने दावा किया कि ''मैं आसियान को एक बड़े हवाई जहाज के रुप में देखता हूँ जिसके एक पंख के रुप में चीन है तो दूसरे पंख के रुप में भारत, यदि दोनों पंख ऊपर उठेंगे तो आसियान रुपी जहाज अपने आप ऊपर उठेगा।

गोह चोक तोंग के सहयोग से भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक साल के अन्दर ''व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते'' को लागू करने के उद्देश्य से एक 'संयुक्त अध्ययन समूह' का गठन किया। जिसकी परिणति भारत–सिंगापुर के बीच जून 2005 ई0 में 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते ;ब्म्ब्।द्ध' के रुप में हुई। सीईसीए आपसी पहचान समझौता ;ड्त्।द्ध के समापन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत उत्पादों का अनुकृति परीक्षण और प्रमाणन समाप्त कर वस्तुओं को संबंधित देशों के बाजारों में बिक्री हेतु लाया जा सकेगा। इस क्षेत्रवार एमआरए से लागत कम आएगी और कम समय में उत्पादों का विपणन किया जा सकेगा। सीईसीए एक एकीकृत समझौता था जो सामान एवं सेवाओं के व्यापार, निवेश संरक्षण जैसे आर्थिक सहयोग के साथ–साथ शिक्षा, बौद्धिक सम्पदा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी संबंधित था।

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता चरणबद्ध तरीके से टैरिफ उन्मूलन के प्रावधान पर अधारित था। जिसमें मुख्य रुप से कृषि एवं वस्त्र उत्पादों सहित 6551 वस्तुओं की एक नकारात्मक सूची को भी सम्मलित किया गया। भारत ने 2005–2009 ई0 के बीच 2202 वस्तुओं को लक्षित करके उन पर से टैरिफ को समाप्त कर दिया और जून 2009 में 2413 वस्तुओं में चरणबद्ध रुप से 50ः तक कमी की।

यह समझौता, भारत–सिंगापुर के बीच व्यापार के सन्दर्भ में बहुत सकारात्मक रहा। जहाँ 2003–04 ई0 में दोनों के बीच व्यापार 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था वहीं 2006–07 ई0 में बढ़कर 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुँच गया। इस बड़े अन्तर का प्रमुख कारण भारत द्वारा 1 अगस्त 2005 ई0 को 506 मदों से सीमा शुल्क का हटाना था। बिना किसी रुकावट के दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। 2005 ई0 में भारत, सिंगापुर का 13वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीरदार, 2008 में 10वाँ एवं 2012 में 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीरदार बन गया।

वर्ष 2007–08 ई0 के दौरान भारत–सिंगापुर के बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण संबंधों को और सवंर्धित करने के लिए अनेक नयी पहलकदमियाँ की गयी। इस संबंध में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर नजर रखने के लिए विदेश मंत्रियों के नेतृत्व में गठित संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति उल्लेखनीय है। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की सिंगापुर

यात्रा के दौरान 19 जून 2007 ई0 को दोनों देशों की वायुसेना द्विपक्षीय अभ्यास और संयुक्त प्रशिक्षण से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की दूसरी समीक्षा 2010 ई0 से प्रारम्भ हुई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हीसिंग लूंग दिसम्बर 2012 ई0 की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष सीका के दूसरे चरण को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं जिससे टैरिफ दरों में और अधिक कमी आएगी। प्रधानमंत्री लूंग ने आगे कहा ''हम आगे बढ़ने और साझेदारी को नया रुप देने के लिए तैयार हैं अगर भारत व्यापार समझौते को और अधिक उदार बनाने को तैयार हो तो हम बैंकिंग क्षेत्र को खोलना चाहते हैं जो पूरा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम श्रम क्षेत्र में भी सुधारों को देख रहे हैं और विमानन क्षेत्र में सहयोग के बारे में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

सिंगापुर की सामरिक स्थिति, भारत–सिंगापुर के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग विकसित करने के प्रमुख कारणें में से एक था। भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत एवं दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच व्यापार की मात्रा बढ़ गयी और यह व्यापार मलक्का जलसंधि से होकर गुजरता है जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर से सामरिक रुप से भारत का जुड़ना आवश्यक हो गया। भारत–सिंगापुर के बीच रक्षात्मक सहयोग 1992 ई0 से प्रारम्भ हुआ और 1993 ई0 से नियमित सैनिक अभ्यास शुरु हुए। 1994 ई0 से दोनों देशों ने द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को संथागत बनाने के लिए एक एमोयू ;डमउवतंदकनउ वि्न्दकमतेजंदकपदहद्ध पर हस्ताक्षर किये गये और भारत ने सिंगापुर नौसेना को भारतीय पनडुब्बियों एवं पनडुब्बी विरोधी युद्ध ;ॅंद्ध के प्रशिक्षण की अनुमति दी। इसी समय ऑपरेशन मिलान ;डप्स्।छद्ध जिसमें सिंगापुर के साथ अन्य आसियान देश भी सम्मिलित थे, वे भी आये।

2003 ई0 में भारत–सिंगापुर के बीच एक रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए गये और 2004 ई0 में भारत ने सिंगापुर की सेना को भारत में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की, जिसे भारत में किसी भी विदेशी सैन्य उपस्थिति को अनुमति न देने के अपने पारंम्परिक स्थिति से पलायन की संज्ञा दी जा सकती है। 11 फरवरी से 5 अप्रैल 2005 ई0 को दिओली एवं बबीना में भारत–सिंगापुर के बीच पहला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया जिसमें ऑरर्म्ड एवं ऑरटिलेरी वाली इकाईयाँ भी सम्मिलित थी। इसके बाद अक्टूबर 2004 ई0 में ग्वालियर में तथा दुबारा जनवरी 2006 ई0 में कोलकता के पास कलाईकुंडा में सिंडैक्स–04 ‶;प्छक्म्.04द्ध द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास, दक्षिणी चीन सागर में सिम्बैक्स–05 ‶;प्डठम्`जंदके वित‶पदहंचवतम प्दकपं डंतपजपउम इपसंजमतंस म्गमतबपेमद्ध तथा अक्टूबर 2009 में अग्नि वैरियर नामक संयुक्त ऑरटिलेरी अभ्यास किया गया। भारत–सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों को एक नया आयाम तब मिला जब फरवरी 2006 ई0 में सिंगापुर ने अपना पहला रक्षा सलाहकार नयी दिल्ली के लिए नियुक्त किया।

भारत–सिंगापुर के बीच 1994 से मई 2017 ई0 तक दोनों देशों की नौसेना द्वारा 24 सिम्बैक्स अभ्यास किए जा चुके हैं जो अब तक भारतीय नौसेना द्वारा किसी देश के साथ किया गया सबसे अधिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एवं सिंगापुर

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो वर्तमान भारत सरकार की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अवयव है, यह कोई नई नीति नही है बल्कि 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का ही परिवर्धित रुप है। इसके अन्तर्गत आर्थिक एवं रणनीतिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पक्ष के साथ, संवाद एवं सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना को भी शामिल किया गया है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे– मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया, स्मार्ट सिटी, एवं स्किल इंडिया से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अतिरिक्त भारत इस नीति के माध्यम से दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों के साथ सुरक्षा संबंधों को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार इस 'एक्ट ईस्ट पालिसी' को भारत के आसियान तथा पूर्वोत्तर के देशों के साथ बढ़ती आर्थिक, रणनीतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक साक्षेदारी के रुप में देखा जा सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नवम्बर 2014 ई0 में भारत–आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान उद्घोषित 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' की सफलता के लिए भारत–सिंगापुर संबंधों को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

भारत–सिंगापुर राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर सिंगापुर के राष्ट्रपति डॉ. टोनी टॉन केंग याम ने 8 से 11 फरवरी, 2015 ई0 के दौरान भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने एवं साझेदारी को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। जिसके तहत् स्मार्ट शहर विकसित करने एवं शहरी जीर्णोद्धार के लिए विशिष्ट पहल, कौशल विकास को बढ़ावा देना, संपर्क एवं तटीय बंदरगाह विकास की गति तेज करने के उपाय तथा भारत में शुरु की गयी विकास की नई पहलों में निवेश बढ़ाने के लिए परियोजनाएँ और भारत के साथ आदान–प्रदान बढ़ाना शामिल था। दोनों देश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता एवं कार्यकुशलता के लिए अनुभव साझा करने के साथ–साथ आतंकवाद से लड़ने में सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमत हुए तथा राष्ट्रपति टैन ने भारत में सिंगापुर महोत्सव का भी शुभारम्भ किया।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हान लूंग ने 7 मई 2015 ई0 को लिटिल इण्डिया में पहला संग्रहालय 'इण्डिया हेरिटेज सेण्टर' की शुरुआत की। यह संग्रहालय भारतीय इतिहास को समर्पित है जिसके लिए भारत सरकार ने चार महान राष्ट्रीय नेताओं– महात्मा गाँधी, जवाहर लाल नेहरु, रबीन्द्रनाथ टैगोर और सुभाषचन्द्र बोस की प्रतिमाएँ भेजी।

24 नवम्बर 2015 ई0 को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान भारत–सिंगापुर के मध्य साइबर सुरक्षा, शिपिंग, समुद्री सुरक्षा आदि के क्षेत्र में 10 समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें रणनीतिक साझेदारी, विकास व स्थिरता को ध्यान में रखते हुए रक्षामंत्री स्तर की बातचीत, संयुक्त सैन्य अभ्यास, साइबर सुरक्षा के तहत् सूचनाओं के आदान–प्रदान पर सहमति बनी। दोनों देशों के मध्य एमओयू के अनुसार नीति आयोग और सिंगापुर कोऑपरेशन एण्टरप्राइज के बीच नगरीय योजना, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड मैनेजमेंट में भागीदारी सरकारी व निजी स्तर पर होगी। इसके अलावा नशीली दवा तस्करी नियंत्रण संबंधी सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किये गये जबकि सांस्कृतिक संबंधों के अन्तर्गत कला, विरासत, आर्काइव व लाइब्रेरी, 2015–18 ई0 के लिए अधिशासी कार्यक्रम, दस्तावेज तैयारी और तकनीकी विशेषज्ञता के आदान–प्रदान पर भी सहमति बनी। भारत एवं सिंगापुर के औद्योगिक संबंधों की 50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक–दूसरे के राष्ट्रपति के भवनों पर एक संयुक्त डाक टिकट जारी किया।

सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने अक्टूबर 2016 के पाँच–दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य औद्योगिक सम्पदा, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित तीन समझौते किये गये तथा लगातार बढ़ रही आतंकी धमकियों से निपटने, व्यापार तथा निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

उपसंहार

दक्षिण–पूर्व एशियाई देशों में सिंगापुर अभी भी भारत का सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है। पिछले दो दशकों से सिंगापुर भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी में महत्वपूर्ण स्थान रखता आ रहा है। यद्यपि भारत 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के द्वारा अपने संबंधों का भौगोलिक विस्तार एशिया से प्रशांत क्षेत्र के देशों तक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में सिंगापुर, भारत के एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति की भूसामरिक पहल के समर्थक के रुप में उभरा है। दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत की सामरिक पहुँच और आर्थिक एकीकरण तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की सैन्य उपस्थिति के लिए सिंगापुर की महत्वपूर्ण भूमिका है। एशिया–प्रशांत क्षेत्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति से चीन का प्रतिरोध करना आसान होगा भारत–सिंगापुर संबंध, भारत को पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने तथा आसियान से संबंध प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आसियान देशों में सिंगापुर, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा सबसे बड़ा निवेशक भी है। एक क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र के रुप में सिंगापुर के बैंकिग एव वित्तीय बाजार पूर्ण रुप से विकसित हैं। यह भारतीय कम्पनियों के लिए पूँजी जुटाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।

सिंगापुर की उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति कई देशों के परिवहन के साथ व्यापक रुप से जुड़ी हुई है। यह भारत के निर्यात के लिए अच्छा परिवहन हब बन सकता है। इसके अलावा सिंगापुर में भी एशिया से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख बाजारों तक पहुँच के लिए मुक्त व्यापार समझौते का एक घना नेटवर्क भारत को उपलब्ध हो सकता है। भारत के पूरक, मानव विविधता का छोड़कर, बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के सिंगापुर निवेश, मानव पूँजी में सुधार तथा ज्ञान एवं कौशल आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने में सफल रहा है, जो भारत के ध्यानाकर्षण का प्रमुख कारण है। इस प्रकार सिंगापुर की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक एवं सामरिक दोनों रुप से भारत के हित के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में जब भारत एशिया–प्रशांत राज्यों के साथ संबंधों को विकसित कर रहा है, सिंगापुर अपने छोटे आकार के बावजूद पूरे क्षेत्र में भारत की सुरक्षा भूमिका के लिए भविष्य में एक धुरी के रूप में कार्य कर सकता है।

REFERENCES

[1]. Murthy, Gautam. (April-June 2009). India and Singapore: Dynamic Economic Partners. Indian Foreign Affairs Journal Vol. 4, No. 2, pp. 38-62.

[2]. World Bank Report on Ease og Doing usiness 2018 available on [http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/Singapore]

[3]. World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2016-17 available on [http://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1/]

[4]. Jha, Pankaj Kumar. (Sep. 2004). India-Singapore Relations. World Focus Vol. 25, No. 9.

[5]. Cencus of Population. (August, 2010). Republic of Singapore: Department of Statistics, Ministry of Trade & Industry.
[6]. Ray, Sunanda K. Dutta. (2009). Looking East to Look West: Lee Kuan Yew's Mission India. , Singapore: Institute of South East Asian Studies.136.
[7]. Sridharan, Kripa. (1996). The ASEAN Region in India's Forign Policy. Aldershot, England: Dartmouth, 41.
[8]. Brewster, David. (2009). India's Security Partnership with Singapore. The Pacific Review 22, No.5. 600.
[9]. Naidu, G.V.C. (April- June 2004). Whither the Look East Policy: India and Southeast Asia. Strategic Analysis, Vol.28, No. 2.
[10]. Hossain, Ishtiaq. (1995). Singapore - India Relations in the Post Cold-War Period: A Singapore Perspective, in Singapore-India Relations: A Primer, edited by Mun Cheong Yong and V.V. Bhanoji Rao. Singapore: Singapore University Press. 65.
[11]. Ong, Catherine. (December 30, 1994). PM's Visit to India comes in Wake of Record Trade, Investments. The Business Times.
[12]. Brewster, David. (2009). India's Security Partnership with Singapore. The Pacific Review 22, No. 5. 604.
[13]. Ibid,
[14]. Garg, Rahul (2009). India - Singapore CECA: An Evaluation. Working paper No. 234. New Delhi: Centre for Civil Society.
[15]. Palit, Dr. Amitendu. (June 16, 2008). India-Singapore Trade Relations. Working papers. ISAS. 6.
[16]. Ibid, 6.
[17]. High Commission of India. (April 4, 2013). India and Singapore Bilateral Trade and Investment. Singapore.
[18]. The Hindu. (December 21, 2012). Second Review of India - Singapore CECA to conclude soon: Lee. New Delhi.
[19]. Bose, Saheli. (December, 2014). India-Singapore Relations: Scaling New Heights. World Focus Vol.35, No.12.
[20]. Jha, Pankaj. (September 2007). India's Emerging Defence cooperation with south East Asia. India Strategic' Vol. 2, No. 9, p. 8.
[21]. Singapore-India Sign Memorendum of Understanding for Army Exercise in India, <http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2005 Accessed on September,12> 2005.
[22]. Jha, Pankaj & Mishra, Rahul. (April-June 2010).Defence Cooperation: A Case Study of India and Singapore. Air Power Journal, Vol.5, o. 2, p.73-96.
[23]. Ibid,76.